भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 4184**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमेरिकी कर नीतियों का प्रभाव

4184. श्री के. राधाकृष्णनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वैश्विक न्यूनतम कर और कॉर्पोरेट कर विनियमों सहित अमेरिकी कर नीतियों में हाल के बदलावों का संयुक्त राज्य अमेरिका में कारोबार करने वाली या निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियों पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने यह आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है कि इन कर उपायों ने भारत के व्यापार संतुलन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह और समग्र आर्थिक विकास को किस प्रकार प्रभावित किया है;

(ग) क्या हाल के महीनों में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के अवमूल्यन ने भारतीय निर्यातकों और अमेरिकी बाजारों में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए चुनौतियों को और बढ़ा दिया है;

(घ) क्या सरकार ने इस मुद्दे को अमेरिकी प्राधिकारियों या अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ उठाया है और भारतीय आर्थिक एवं वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) वैश्विक कराधान घटनाक्रमों के मद्देनजर प्रभावित क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने, निर्यात प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और रुपये को स्थिर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक दोहरा कराधान परिहार करार किया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय कंपनियों के कॉर्पोरेट कराधान पर लागू होता है। इस करार में उपलब्ध लाभ संयुक्त राज्य अमेरिका के घरेलू कानूनों के बावजूद अपरिवर्तित रहेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी तक वैश्विक न्यूनतम कर नियमों को लागू नहीं किया है, और कहा है कि पूर्ववर्ती प्रशासन द्वारा इस पर की गई प्रतिबद्धता का संयुक्त राज्य अमेरिका में तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा जब

तक कि उन्हें उसके घरेलू कानूनों में अपना नहीं लिया जाता है। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय कंपनियों के कराधान पर प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। अमेरिकी कॉर्पोरेट कर संबंधी बदलाव आम तौर पर अमेरिकी कर देयता वाली संस्थाओं पर लागू होते हैं और इससे भारत से बिक्री करने वाले निर्यातकों पर सीधे प्रभाव पड़ने की प्रत्याशा नहीं है।

(ख): व्यापार संतुलन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह और आर्थिक विकास जैसे संकेतक कई अलग-अलग परिवर्ती कारकों पर निर्भर करते हैं। व्यापार संतुलन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार योग्य वस्तुओं की मांग और आपूर्ति सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। किसी विशिष्ट विदेशी देश में कर नीति में परिवर्तन का उपरोक्त संकेतकों पर प्रभाव, यदि कोई हो, को अलग-थलग नहीं किया जा सकता है।

(ग) से (च): अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के अवमूल्यन का अर्थव्यवस्था पर समग्र प्रभाव कई कारकों पर निर्भर करता है और इसे अलग-थलग नहीं किया जा सकता।

सरकार देश के आर्थिक और वाणिज्यिक हितों की रक्षा करने और निर्यात संवर्धन एवं व्यापार विविधीकरण सहित सभी उचित कदमों के माध्यम से व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए उद्योग सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर कार्य कर रही है।

आरबीआई बाह्य व्यापार और भुगतान को सुगम बनाने तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और अनुरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मौद्रिक नीति तैयार करती है, उसे लागू करती है और उसकी निगरानी करती है। आरबीआई ने विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा वित्तपोषण के स्रोतों में विविधता लाने और उनका विस्तार करने के लिए भी कई उपाय किए हैं।

*****